RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 23 SEPTEMBER TO 29 SEPTEMBER 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 5 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

आईओसी गुजरात रिफाइनरी विस्तार, पेट्रोरसायन परियोजना में 17,825 करोड़ रुपये करेगी निवेश Page 2

बेहतर मानव संसाधनों के अभाव से जूझता भारत Page 5

कोविड-19 टीके के लिए विनिर्माण सुविधाओं पर 5 हजार करोड़ रुपये तक निवेश की जरूरत: जायडस कैडिला Page 7

editoria!

कर्ज का बढ़ता बोझ

वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार का कुल कर्ज पहली बार 100 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। यह तिमाही रिपोर्ट बताती है कि कर्ज का यह बोझ अपनी सामान्य रफ्तार से ही बढ़ रहा था, मगर कोरोना और लॉकडाउन के चलते इसमें काफी तेजी आ गई। अप्रैल से जून तिमाही में उठाए गए कर्ज में सात लाख करोड़ का अचानक इजाफा होने से यह 100 लाख करोड़ की मनोवैज्ञानिक सीमा पार कर गया। यह खबर एकबारगी सबका ध्यान जरूर खींचती है लेकिन वित्तीय मामलों के जानकार शायद ही इसे अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात मानें। तीन ट्रिलियन डॉलर (करीब 230 लाख करोड़ रुपये) के जीडीपी वाले देश के लिए 100 लाख करोड़ (43 फीसदी) का कर्ज सामान्य स्थिति में चिंता की बात क्यों मानी जानी चाहिए? खासकर तब, जब अमेरिका जैसे देश में कर्ज जीडीपी के 106 फीसदी से ऊपर और जापान में 246 फीसदी से ऊपर हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की दिसंबर में आई रैंकिंग के हिसाब से देखें तो कर्ज के बोझ के मामले में भारत का स्थान 170 देशों में 94 वां है। लेकिन कागजी बातों के आधार पर खुद को भुलावे में रखना भी ठीक नहीं होगा। अमेरिका और जापान जैसे देशों से भारत की स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह वित्त घाटे और व्यापार घाटे के दोहरे दबाव में चलने वाली अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह कि देश की जीडीपी ग्रोथ गंभीर रूप से नेगेटिव हो चुकी है। माइनस 23.9 की मौजूदा दर से ऊपर उठकर अगली तिमाहियों में हम बेहतरी की ओर बढ़ने लगें तो भी कोरोना के माहौल में तुरंत और तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में जहां राजस्व वसूली में कमी आनी तय है, वहीं यह भी निश्चित है कि रिकवरी के लिए सरकार को खर्च बढ़ाना होगा, जिसका एकमात्र तरीका फिलहाल और ज्यादा कर्ज लेना ही हो सकता है। यानी निकट भविष्य में कर्ज का बोझ बढ़ने ही वाला है। प्रसंगवश याद किया जा सकता है कि कर्ज के जाल (डेट ट्रैप) में फंसने की आशंका अस्सी के दशक में सार्वजनिक चर्चा का विषय हुआ करती थी। डेट ट्रैप तकनीकी तौर पर वह स्थिति है, जब एक देश को अपने कर्ज की किस्तें और ब्याज अदा करने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। नब्बे के दशक में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने इस चर्चा को अतीत की बात बना दिया था। अभी, तीन-चार दशक बाद बेहद असामान्य स्थितियों में कर्ज पर चर्चा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनी है लेकिन न तो ये हालात स्थायी हैं और न ही इस चर्चा से परेशान होने की कोई जरूरत है। महामारी के संकट से उबरते हुए हम जैसे-जैसे विकास की अपनी पिछली रफ्तार के करीब पहुंचेंगे वैसे-वैसे ये चुनौतियां छंटने लगेंगी। हालांकि उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न स्रोतों से लिए जा रहे कर्ज के इस्तेमाल में किसी तरह की लापरवाही न हो और उसे पॉप्युलिज्म की भेंट न चढ़ने दिया जाए।

नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे का जोरदार विरोध

गो बैक चाइना के लगे नारे

काठमांडू। एजेंसी

नेपाल के हुमला इलाके में चीन के 9 बिल्डिंग्स के निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख?या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं और गो बैक चाइना के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लिया हुआ है जिस पर लिखा, 'बैक ऑफ चाइना'। उन?होंने चीन से मांग की कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद करे। प्रदर्शनकारियों ने चीन से पुरानी संधि को लागू करने की भी मांग की। बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तेजी से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। वहीं, ड्रैगन भी उनकी जमीन पर उसी तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। नेपाली मीडिया में चीन के घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी गई है।

सरकारी अधिकारी ने चीनी घुसपैठ की पुष्टि की

नेपाल की वेबसाइट खबरहब डॉट काम की एक रिपोर्ट के अनुसार, हुमला के सहायक मुख्य जिला अधिकारी दलबहादुर हमाल ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लापचा-लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन के बनाए हुए 9 बिल्डिंग्स दिखाई दिए। हालांकि नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में पहले एक बिल्डिंग का ही जिक्र था, लेकिन निरीक्षण के बाद वहां ऐसी ही 8 और बिल्डिंग्स पाई गई हैं।

हमेशा से उपेक्षित रहा है नेपाल का यह क्षेत्र

हमाल जिले का लापचा-लिपू क्षेत्र मुख्यालय से दूर होने के कारण हमेशा से उपेक्षित रहा है। नेपाल ने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बुनियादी ढाचे का निर्माण नहीं किया है। नेपाली अधिकारी इस क्षेत्र का कभी दौरा भी नहीं करते हैं। चीन ने नेपाल की इसी बात का फायदा उठाकर उसकी क्षेत्र में इन बिल्डिंग्स का निर्माण किया है।

जिला प्रशासन ने गृह मंत्रालय को भेजी चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट

अपने निरीक्षण के बाद हमाल के जिला प्रशासन कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट नेपाल के गृह मंत्रालय को भेज दी है। इसमें नेपाली क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वहीं, दबाव बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को नेपाली विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। माना जा रहा है कि नेपाल सरकार जल्द ही चीनी अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाएगी।

पहले चीन की एक ही बिल्डिंग की थी जानकारी

हमाल जिला प्रशासन की निरीक्षण टीम में शामिल एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हम चीन की इन इमारतों को दूर से देख सकते थे। हमने चीन द्वारा वहां बनाई जा रही एक इमारत के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन हमारी यात्रा में आठ और पाए गए हैं।

भारत ने सस्ते तेल से रणनीतिक भंडारों को भरकर 5,000 करोड़ रुपये की बचत की: प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल कीमतों के दो दशक के निम्न स्तर पर पहुंचने के दौरान अप्रैल-मई में कच्चे तेल की खरीद कर तीन रणनीतिक कच्चे तेल भंडारों को भर कर सरकार ने करीब 5,000 करोड़ रुपये की बचत की है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है जिसने अपनी किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए तीन स्थानों पर कच्चे तेल के भूमिगत रणनीतिक भंडारण तैयार किये हैं। प्रधान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा उठाते हुए, भारत ने अप्रैल-मई, 2020 में एक करोड़ 67 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद करते हुये विशाखापत्तनम, मैंगलोर, और पाडुर में बनाए गए तीन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को भरा।" इस साल जनवरी में कच्चे तेल का दाम 60 डॉलर प्रति बैरल की तुलना में अप्रैल- मई के दौरान खरीदे गये कच्चे तेल की औसत लागत 19 डॉलर प्रति बैरल रही। उन्होंने कहा कि इससे 68 करोड़ 51.1 लाख डॉलर यानी 5,069 करोड़ रुपये की बचत हुई। उल्लेखनीय है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के दौरान कच्चे तेल की मांग में गिरावट आने से इसके दाम नीचे आ गये थे।

अमीर देश कुवैत में कैश की किल्लत!

मूडीज ने पहली बार डाउनग्रेड की रेटिंग

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कुवैत आजकल नगदी संकट से जूझ रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हायर लिक्विडिटी रिस्क और कमजोर गवर्नेंस तथा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का हवाला देते हुए कुवैत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। यह पहला मौका है जब मूडीज ने कुवैत की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है।

खाड़ी देश कुवैत के पास तेल का अकूत भंडार है लेकिन तेल की कीमत में कमी से उसकी इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुवैत को इंटरनेशनल डेट जारी करने की अनुमति देने वाला कानून पारित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। डीज ने कहा कि कानून के अभाव में कुवैत डेट जारी नहीं कर सकता है और न ही फ्यूचर जेनरेशंस फंड में सॉवरेन वेल्थ फंड ले सकता है। देश के पास जो नगदी उपलब्ध है वह निपटने वाली है। मजबूत वित्तीय स्थिति के बावजूद देश में लिक्विडिटी रिस्क पैदा हो रहा है।

क्या है नगदी किल्लत की वजह

यही वजह है कि मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने कुवैत की रेटिंग A1 से घटाकर Aa2 कर दी। पिछली बार कुवैत ने जब 2017 में इंटरनेशनल मार्केट में डेट जारी किया था तो उसके बॉन्ड्स ने अबु धाबी द्वारा इश्यू पेपर के बराबर ट्रेड किया था। तेल संपदा के कारण कुवैत की फाइनेंशियल वेल्थ से निवेशकों ने इसमें भरोसा दिखाया था। लेकिन 140 अरब डॉलर की इकॉनमी पर अब 46 अरब डॉलर के घाटे की तलवार लटक रही है। कोरोना वायरस संकट, तेल की कीमतों में कमी, नए कर्ज कानून को लेकर सरकार और संसद में तकरार से सरकारी खर्च में तेजी नहीं आ पा रही है।

आईओसी गुजरात रिफाइनरी विस्तार, पेट्रोरसायन परियोजना में 17,825 करोड़ रुपये करेगी निवेश

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के साथ पेट्रोरसायन संयंत्र की स्थापना के लिये 17,825 करोड़ रुपये निवेश करेगी। कंपनी मार्जिन को बनाये रखने के लिये पेट्रोरसायन कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। शेयर बाजार को दी सूचना में आईओसी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की 21 सितंबर को हुई बैठक में गुजरात रिफाइनरी परिसर में पेट्रोरसायन और ल्यूब इंटीग्रेशन परियोजना को मंजूरी दे दी गयी। इस पर 17,825 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। परियोजना के तहत गुजरात में वडोदरा रिफाइनरी की क्षमता 1.37 करोड़ टन सालाना से बढ़ाकर 1.8 करोड़ टन सालाना करने का प्रस्ताव है। साथ ही 5 लाख टन सालाना क्षमता का प्रॉपीलीन (पीपी) संयंत्र और 2,35,000 टन सालाना ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक (एलओबीएस) यूनिट की परिकल्पना की गयी है। कंपनी के अनुसार यह परियोजना भविष्य में प्रमुख रसायनों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह आईओसी के कॉर्पोरेट मार्जिन को बढ़ाएगा। सोमवार को कंपनी की सलाना बैठक के बाद आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने संवाददाताओं से कहा था कि आईओसी पेट्रोरसायन विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है और कपड़ा कारोबार में कदम रखने पर विचार कर रही है। वैद्य ने कहा, "गुजरात रिफाइनरी परियोजना आईओसी की पेट्रोरसायन क्षमता को अगले दशक तक 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। फिलहाल यह 32 लाख टन सालाना है।" उन्होंने कहा था, "पेट्रोरसायन उत्पादन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक आकर्षक अवसर है क्योंकि प्रति व्यक्ति खपत अभी भी काफी कम है।" वैद्य के अनुसार इससे मार्जिन और तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचाव में मदद मिलेगी। आईओसी वर्तमान में ओडीशा की पारदीप रिफाइनरी में एथलिन ग्लायकोल परियोजना को अमल में ला रही है। इसके साथ ही यहां पैराजायिलन..प्यूरीफाइड टेरेप्थालिक एसिड (पीएक्स..पीटीए) प्लांट भी लगाया जा रहा है। गुजरात रिफाइनरी और हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी में भी विस्तार कार्य चल रहे हैं। कंपनी इन सभी परियोजनाओं पर 28,869 करोड़ रुपये निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ओडिशा के भद्रक में 1,970 करोड़ रुपये की लागत से कपड़ा विनिर्माण परियोजना लगाने की भी योजना बना रही है।

आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल, जानें महानगरों में इसके भाव

नयी दिल्ली। एजेंसी

आज भी पेट्रोल की कीमत में उछाल आया है। हालांकि, डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महानगरों में पेट्रोल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81.49 रुपये प्रति लीटर है। कल यह कीमत 81.35 रुपये प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर है।

ये हैं महानगरों के रेट

आज मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 88.16 रुपये, कोलकाता में 83.01 रुपये, चेन्नै मे 84.52 रुपये और नोएडा में 81.94 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो मुंबई में एक लीटर डीजल की कीमत 80.11 रुपये, कोलकाता में 77.06 रुपये, चेन्नै में 78.86 रुपये और नोएडा में 73.73 रुपये है।

इस सप्ताह पेट्रोल 92 पैसे महंगा

इस सप्ताह में पेट्रोल करीब 92 पैसा प्रति लीटर और डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है। हर सुबह 6 बजे इसकी कीमत अपडेट हो जाती है।

सेंसेक्स 66 अंक टूटा, भारती एयरटेल का शेयर 8 प्रतिशत लुढ़का

मुंबई। शेयर बाजारों में पांच दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 66 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बावजूद भारती एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस में गिरावट से शेयर बाजार नीचे आ गया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला लेकिन कारोबार के दौरान यह तेजी बरकरार नहीं रह पायी। अंत में सेंसेक्स 65.66 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37,668.42 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21.80 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,131.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में भारती एयरटेल रही। इसमें करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अलावा टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, पावरग्रिड, ओएनजीसी और टीसीएस में भी गिरावट दर्ज की गयी।

दूसरी तरफ जिन प्रमुख शेयरों में तेजी रही, उनमें एक्सिस बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। कारोबारियों के अनुसार सकारात्मक वैश्विक रुख के बावजूद शेयर केंद्रित बिकवाली से घरेलू बाजार में गिरावट रही। वैश्विक स्तर पर एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग और दक्षिण कोरिया का सोल बाजार लाभ में रहे जबकि जापान में तोक्यो नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ 42.09 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। विदेशी विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया एक पैसे की हल्की बढ़त के साथ 73.57 पर बंद हुआ।

रिलायंस रिटेल में केकेआर करेगा रू. 5,550 करोड़ का निवेश

रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक के बाद यह दूसरा बड़ा निवेश है केकेआर ने इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया था

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक निवेश फर्म केकेआर 1.28₹ इक्विटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ('आरआरवीएल') में 5,550 करोड़ रूपय का निवेश करेगी। यह रिलायंस रिटेल में दूसरा बड़ा निवेश है। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ('आरआरवीएल') ने इस निवेश की घोषणा की। सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री-मनी इक्विटी को 4.21 लाख करोड़ रूपय आंका गया। साल की शुरुआत में केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ का निवेश किया था। यह केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी में दूसरा निवेश है।

रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर मे फैले 12 हजार से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीददार आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। रिलायंस रिटेल के पास देश के सबसे लाभदायक रिटेल बिजनेस तमगा भी है। कंपनी खुदरा वैश्विक और घरेलू कंपनियों, छोटे उद्योगों, खुदरा व्यापारियों और किसानों का एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहती है, जिससे उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर सेवा प्रदान की जा सके और लाखों रोजगार पैदा किए जा सकें। रिलायंस रिटेल ने अपनी नई वाणिज्य रणनीति के तहत छोटे और असंगठित व्यापारियों का डिजिटलीकरण शुरू किया है। कंपनी का लक्ष्य 2 करोड़ व्यापारियों को इस नेटवर्क से जोड़ना है। यह नेटवर्क व्यापारियों को बेहतर टेक्नॉलोजी के साथ ग्राहकों को बेहतर मूल्य पर सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, 'मैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में केकेआर का स्वागत करते हुए प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। प्रत्येक भारतीय के लाभ के लिए हम भारतीय रिटेल ईको-सिस्टम को विकसित करने और बदलने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपने डिजिटल सेवाओं और रिटेल बिजनेस में केकेआर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री नॉलेज और ऑपरेशनल एक्सपर्टिस का लाभ लेने को तैयार हैं'

केकेआर के सह-संस्थापक और सह-सीईओ हेनरी क्राविस ने कहा, 'हम रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इस निवेश के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल सभी व्यापारियों को सशक्त बनाने और भारतीय उपभोक्ताओं के रिटेल खरीददारी के अनुभव को बदल रहा है। । हम भारत के अग्रणी रिटेलर बनने और एक और समावेशी भारतीय रिटेल इकोनॉमी बनाने के रिलायंस रिटेल के मिशन का पूर्ण समर्थन करते हैं। '

सीमा पर पंगा चीन को पड़ा महंगा भारत को निर्यात में आई भारी गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के बीच चीन से आयात में काफी गिरावट आई है। अप्रैल से जुलाई के बीच चीन से आयात 16.60 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 23.45 अरब डॉलर रहा था।

चीन से आयात में आई है गिरावट

गलवान घाटी की घटना के बाद चीन से आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल-अगस्त के बीच चीन से आयात में करीब 28 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, अगस्त के महीने में चीन से 4.98 अरब डॉलर और जुलाई के महीने में 5.58 अरब डॉलर का आयात किया गया था।

देश के निर्यात में हो रहा है सुधार

पीयूष गोयल ने अलग से यह भी कहा कि चीन को मिले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने को लेकर फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। बाद में मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा कि देश का निर्यात काफी तेजी से विकास कर रहा है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया एक पैसे की मजबूती के साथ बंद

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के बीच निवेशकों के सतर्क रुख के चलते रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसे की बढ़त के साथ 73.57 (अनंतिम) के भाव पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोरी के साथ 73.59 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान उसमें एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। रुपया अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसे की बढ़त के साथ 73.57 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान रुपये ने 73.49 के ऊपरी स्तर और 73.63 के निचले स्तर को देखा। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ 73.58 पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती से भी घरेलू मुद्रा पर दबाव बना। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.19 प्रतिशत गिरकर 41.64 डालर प्रति बैरल पर था।

जीएसटी में कटौती से दोपहिया वाहन उद्योग को मिलेगी रफ्तार : एचएमएसआई

नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने दोपहिया वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती को लेकर उद्योग के विभिन्न हलकों की मांग का समर्थन किया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम से चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल का सामना कर रहे क्षेत्र को पटरी पर लाने और उसकी वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। जापान की वाहन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि क्षेत्र आर्थिक नरमी के कारण इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों के कारण क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हुई है। एचएमएसआई के निदेशक (बिक्री और विपणन) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ''हमें भरोसा है कि इस प्रकार के कदम से खरीदारों के लिये वाहन सस्ता होगा और इससे उनकी बचत बढ़ेगी।'' उनसे यह पूछा गया था कि क्या दोपहिया वाहनों पर जीएसटी में कटौती से क्षेत्र को पटरी पर लाने में मदद मदद मिलेगी। गुलेरिया ने कहा, ''इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। उद्योग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में जीएसटी में कटौती से उद्योग की वृद्धि को गति मिलेगी।'' उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि लोग आर्थिक नरमी से जुड़ी अनिश्चितता के दौरान नकद अपने पास संभाल कर रखना चाहते है। साथ ही कोविड-19 स्थिति को देखते हुए अपना वाहन लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर दोपहिया वाहन सस्ता होता है, तो इससे उन्हें मदद मिलेगी।'' दोपहिया वाहन उद्योग जीएसटी 28 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत करने की मांग कर रहा है। उसकी दलील है कि दोपहिया वाहन मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आने वाले लाखों परिवार के लिये परिवहन के लिये एक बुनियादी जरूरत है। गुजरात में नव-निर्मित असेंबली लाइन से उत्पादन के बारे में पूछे जाने पर गुलेरिया ने कहा कि ढांचागत सुविधा तैयार है लेकिन इकाइयों के उत्पादन में समय लगेगा।'' उन्होंने कहा, ''अभी हमारे पास कारखानों में पर्याप्त क्षमता है। ऐसे में हम वहां अभी उत्पादन शुरू नहीं करने जा रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार का रुख क्या होता है। बाजार की स्थिति अगर सुधरती है, तब हम वहां से उत्पादन शुरू करने को तैयार हैं।'' कंपनी स्कूटर खंड में पहले से मजबूत है। अब वह देश में मोटरसाइकिल कारोबार में विस्तार पर ध्यान दे रही है। कंपनी की मोटरसाइकिल खंड में बाजार हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है। इस बारे में गुलेरिया ने कहा, ''यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें बिक्री नेटवर्क के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो पर ध्यान देना है।'' उत्पादों के बारे में उन्होंने कहा कि कंपनी को सस्ती और महंगी दोनों स्तर की मोटरसाइकिल लानी होगी। गुलेरिया ने कहा, ''हमें दोनों स्तरों पर विस्तार की जरूरत है। कम कीमत वाले उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिये होंगे। हम सस्ती मोटरसाइकिल पेश करेंगे। लेकिन साथ ही हमने एक्स ब्लेड, होर्नेट 2.0 जैसे उत्पाद पेश कर प्रीमियम खंड में विस्तार शुरू कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि कंपनी के बाइक खंड में बिक्री नेटवर्क के विस्तार की भी जरूरत है। कंपनी बाजार स्थिति में सुधार के साथ इस ओर विशेष ध्यान देगी।

एचडीएफसी बैंक लगातार 7 वें वर्ष के लिए भारत का नंबर 1 ब्रांड घोषित

3.40 मिलियन उपभोक्ता ओं ने 1140 भारतीय ब्रांडों के लिए सर्वेक्षण किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एचडीएफसी बैंक को लगातार सात वें साल भारत के सब से मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया है और '2020 ब्रांड्ज टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स' सर्वेक्षण में इस की कीमत 20.3 बिलियन बताई गई है । एचडीएफसी बैंक का ब्रांड मूल्य पिछले सात वर्षों में 2014 में 9.4 बिलियन डॉलर से 2020 तक 20.3 बिलियन होग या है। इस साल के सर्वेक्षण में, 3.8 श्रेणियों में 3.8 मिलियन भारतीय ब्रांडों ने 3.8 मिलियन भारतीय उपभोक्ता ओं ने भाग लिया और उन का नामांकन किया। ब्रांड्ज की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'एचडीएफसी बैंक ने अपनी वित्तीय दक्षता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, जो 2020 ब्रांड्ज़रू (BrandZ™) कीटॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्टमें 59वें स्थान पर है। 'यह रैंकिंग वैश्विक संचार सेवाओं बेथ के साथ डब्लूपीपी समूह की कंपनी अमार वर्ड ब्राउन द्वारा किएगए सर्वेक्षण पर आधारित है।' विश्व स्तर पर ब्रांडों की असली परीक्षा महामारी के बाद हुई क्यों कि भारत जैसे देश में, कोविद -19 के लॉन्च से पहले भी, मंदी के बादल थे। ब्रांड्ज के अध्यक्ष और स्टोर डब्लू पीपी, इमइए के सीईओ श्री डेविड रोथ ने कहा, 'कई भारतीय ब्रांडों ने इस चुनौती को उठाया है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवाचार काउपयोग करके अपनी वैश्विक पहुंच को साबित कियाहै। हमारे शोध से पता चलता है कि एक बार फिर कंपनियां आगे आई हैं जिन्होंने लगातार ब्रांड निर्माण में निवेश किया है, जिसने उन्हें चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में भी जीवित रहने और अधिक कुशलता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। एचडीएफसी बैंक लगातार छह वर्षों के लिए शीर्ष 100 वैश्विक ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है।एचडीएफसी इस वर्ष 60 वें स्थान से एक पायदान आगे 59 वें स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष 10 ब्रांडों में क्रमशः एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वीजा, अलीबाबा, टेनसेंट, फेसबुक, मैकडॉनल्ड्स, मास्टरकार्ड हैं।

क्या 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद हो गई है? जानें वित्त मंत्री ने क्या कहा

नई दिल्ली। क्या 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है, इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कहा कि 2000 करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नोटों की छपाई को लेकर सरकार रिजर्व बैंक से सलाह लेकर कोई फैसला लेती है।

छपाई का काम दोबारा शुरू

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक पूरे देश में 2 हजार के 27 हजार 398 लाख नोट्स प्रचलन में थे। 31 मार्च 2019 को यह संख्या 32 हजार 910 लाख थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई तात्कालिक रूप से रोक दी थी। अब चरणवार तरीके से यह काम शुरू किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान नोटों की छपाई बंद रही

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) रिजर्व बैंक के लिए नोट छपाई का काम करती है। 23 मार्च से 3 मई तक छपाई का काम रोक दिया गया था। 4 मई से चरणबद्ध तरीके से दोबारा यह काम शुरू किया गया है।

ईपीएफओ ने जुलाई में रिकार्ड 8.45 लाख नये अंशधारक जोड़े

नयी दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुलाई में शुद्ध रूप से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या बढ़कर 8.45 लाख पहुंच गयी जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.82 लाख था। रविवार को जारी यह आंकड़ा बताता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति सुधर रही है। ईपीएफओ के नियमित वेतन पाने वालों के ये आंकड़े कोविड-19 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ईपीएफओ के पेरोल यानी नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के पिछले महीने जारी अस्थायी आंकड़े में शुद्ध रूप से इस साल जून में 6.55 लाख पंजीकरण की बात कही गयी थी। इस आंकड़े को अब संशोधित कर 4,82,352 कर दिया गया है। मई में जारी पेरोल आंकड़े के अनुसार ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण मार्च 2020 में घटकर 5.72 लाख पर आ गया जो फरवरी में 10.21 लाख था। जारी ताजा आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से पंजीकरण नकारात्मक दायरे में था और इसमें 61,807 की गिरावट आयी। जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 20,164 था। इसका मतलब है कि अप्रैल में जितने लोग ईपीएफओ से जुड़े, उससे कहीं अधिक लोग उससे बाहर हुए। इससे पहले जुलाई में अस्थायी आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से एक लाख नये पंजीकरण की बात कही गयी थी। उसे बाद में अगस्त महीने में संशोधित कर 20,164 कर दिया गया। ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण औसतन हर महीने करीब 7 लाख रहता है। ताजा पेरोल आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध रूपसे नये अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी। ईपीएफओ नये अंशधारकों का पेरोल आंकड़ा अप्रैल 2018 से जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 से आंकड़े लिये गये हैं। आंकड़े से यह भी पता चलता है कि सितंबर 2017 से जुलाई 2020 के दौरान शुद्ध रूप से नये अंशधारकों की संख्या 1.68 करोड़ रही। ईपीएफओ का कहना है कि पेरोल आंकड़ा अस्थायी है और इसका अद्यतन होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आने वाले महीनों में अद्यतन किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार आंकड़ा शुद्ध रूप से जुड़े सदस्यों पर आधारित है। इन अनुमानों में अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जिनका योगदान हो सकता है पूरे साल जारी नहीं रहे। ईपीएफओ संगठित/अर्द्ध-संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है। इसके सक्रिय सदस्यों (जिनका योगदान वर्ष के दौरान कम-से-कम एक महीने आता है) की संख्या छह करोड़ है।

तो छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा आर्थिक पैकेज, कैट ने की है मांग

नई दिल्ली। कोरोना काल (Corona Period) में अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इससे छोटे कारोबारी (Small Traders) भी अछूते नहीं हैं। इसी को देखते हुए देश के करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार की तरफ से इन्हें कोई आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो देश भर में लगभग 1.75 करोड़ दुकानों का शटर डाउन हो जाएगा।

रिटेल व्यापार में सुधार जरूरी

संगठन ने आज प्रधानमंत्री को भेजे एक ज्ञापन में आग्रह किया कि तेजी से परिवर्तित हो रहे व्यापार करने के तौर-तरीकों को देखते हुए देश के रिटेल व्यापार में अनेक सुधार आवश्यकता है। इससे ही रिटेल व्यापार व्यवस्थित रूप से चलेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे व्यापारियों को सुविधाएं मिले। इससे करदाताओं का दायरा बढ़ेगा और अंततः सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

40 करोड़ लोगों को मिलता है रोजगार

प्रधानमंत्री को भेजे अपने ज्ञापन में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा है कि देश भर में करीब 7 करोड़ व्यापारी लगभग 40 करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं। ये व्यापारी हर वर्ष लगभग 60 लाख करोड़ रुपये का व्यापार करते हैं। इतना होते हुए भी अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण सेक्टर सदा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। यदि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है तो इस सेक्टर को मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित हर सेक्टर को सरकार ने वित्तीय पैकेज दिया, किन्तु 20 लाख करोड़ के पैकेज में व्यापारियों के ,लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

28 तरह का लेना होता है लाइसेंस

भरतिया का कहना है कि देश का रिटेल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इस समय तरह तरह के कानून हैं। इनमें से कई कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। आज की तारीख में इन कानूनों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय व्यापार करने के लिए 28 से भी अधिक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसे समाप्त कर एक लाइसेंस लेने की व्यवस्था हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रिटेल व्यापार में काम कर रहे व्यापारियों का सही आंकड़ा जानने के लिए शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट कानून (Shop & Establishment Act) में सभी व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और उन्हें एक नंबर दिया जाए जो नंबर हर जगह देना अनिवार्य हो।

आसुस ने भारत में कमर्शियल पीसी मार्केट में प्रवेश की घोषणा की

प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के साथ 'एक्सपर्ट सीरीज' ब्रांड लॉन्च किया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ताइवान में हेडक्वार्टर वाली मल्टीनेशनल कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की भारतीय ब्रांच आसुस इंडिया ने आज आसुस एक्सपर्ट बुक और आसुस एक्सपर्टसेंटर के ब्रांड अम्ब्रेला के नीचे भारत में कमर्शियल पीसी प्रोडक्ट्स का एक विस्तृत पोर्टफोलियो के लॉन्च की घोषणा की है।

आसुस 2020 में भारत में कंज्यूमर पीसी में सबसे तेजी से बढ़ रहा ब्रांड है और इसने 2020 के क्यू2 में टॉप 3 कंज्यूमर पीसी ब्रांड्स क्लब में इंट्री ले ली है। एक्सपर्ट सीरीज कमर्शियल पीसी के लॉन्च के साथ भारत में एंटरप्राइज कस्टमर्स को अत्याधुनिक तकनीक के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का विकल्प मिलेगा। यह आसुस की ओर से मेड फॉर इंडिया पहल के तहत भारतीय एंटरप्राइज़ कंज्यूमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर कस्टमाइज्ड किया गया है।

कमर्शियल पीसी की आसुस एक्सपर्ट सीरीज को एंटरप्राइज और बिजनेस के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। तेजी से बढ़ रहे बिजनेस को आईटी जरूरतों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यह मांग तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि आसुस के सभी एक्सपर्टी सीरीज कमर्शियल प्रोडक्ट्स को क्वालिटी, विश्वसनीयता और लचीलेपन के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि बिजनेसेस के आईटी निवेश के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के रिटर्न के अंतिम उद्देश्य के साथ इन चुनौतियों को दूर कर सकें। आसुस एक्सपर्ट सीरीज बिजनेस और प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए बेजोड़ तकनीक, परफॉर्मेंस, टिकाऊपन और डिज़ाइन प्रदान करता है। इसलिए आसुस एक्सपर्ट सीरीज इंटेलरुकोर प्रोसेसर से संचालित है।

11 मॉडलों के विशाल पोर्टफोलियो के साथ सभी प्रमुख एंटरप्राइज कस्टमर सेग्मेंट्स को टारगेट करता है, जिसमें 10वीं जनरेशन इंटेलरु प्रोसेसर और विंडोज 10 प्रो सपोर्ट वाले लैपटॉप, डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन में वेरिएंट हैं।

मुख्य पॉइंट्स

आसुस एक्सपर्ट सीरीज- नई पीढ़ी की नवीनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित, कमर्शियल पीसी के आसुस एक्सपर्ट सीरीज बिजनेस यूजर्स केन् लिए इनोवेटिव अत्याधुनिक तकनीकी समाधान पेश करेगी, जो इसके लिए पीसी बिजनेस में 30 साल की इंटिग्रेटिंग इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। शैक्षिक संस्थानों, सरकार, माइक्रो बिजनेस, व्यवसायों, एसएमबी और बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों सहित सभी आकारों के व्यवसायों की सेवा करते हुए आसुस उनकी कंप्यूटिंग संबंधी जरूरतों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करेगा

आसुस एक्सपर्टबुक बी9- 10वीं जनरेशन इंटेलरु कोर आई7 प्रोसेसर और 24 घंटे बैटरी बैकअप के साथ दुनिया का सबसे हल्का और सबसे शक्तिशाली बिजनेस लैपटॉप, जो बीस्पोक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रदान करता है

आसुस एक्सपर्टबुक पी2- एनवीडिया डिस्क्रीट ग्राफिक्स और 10वीं जनरेशन इंटेलरु कोर आई7 प्रोसेसर के साथ अपने सेग्मेंट में सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल बिजनेस लैपटॉप

आसुसप्रो एक्सपर्टबुक पी1 सीरीज़- 14' और 15' की किफायती सीरीज़ जिसमें सेग्मेंट के प्रमुख फीचर्स जैसे एफएचडी डिस्प्ले जैसे पतले बेज़ेल्स, फिंगरप्रिंट सेंसर और 10 वीं जनरेशन इंटेलरुकोर आई5 प्रोसेसर है

आसुसप्रो एक्सपर्टसेंटर डेस्कटॉप सीरीज- बिजनेस डेस्कटॉप विशेष रूप से एंटरप्राइज, संगठनात्मक, सरकारी इस्तेमाल, एसएमबी और एसओएचओ के लिए डिज़ाइन किए हैं जो सभी बिजनेस जरूरतों को पूरा करते हैं

आसुस एआईओ सीरीज़ - बहुत ही स्लिम-बेजल नैनोएज एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले के साथ शानदार ऑल-इन-वन पीसी, सेग्मेंट में लीडिंग ऑडियो, वायरलेस पेरिफेरल्स जो 10वीं जनरेशन इंटेलरुकोर आई5 प्रोसेसर का ,सपोर्ट करता है

डेडिकेटेड एंटरप्राइज हेल्पलाइन और सर्विस पैकेज - आसुस के एक्सपर्ट सीरीज पीसी की बिक्री और सेवा के लिए नई डेडिकेटेड हेल्पलाइन की स्थापना की गई है जो सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच (18002678901) में उपलब्ध है। आसुस ने एक्सपर्ट सीरीज़ और ऑप्शनल सर्विस पैकेजों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, प्रायरिटी सर्विस और हार्ड डिस्क रिटेंशन सहित इनेबल्ड सर्विस सपोर्ट दिया है।

राज्यसभा ने दिवाला कानून में संशोधन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

राज्यसभा ने शनिवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च से छह महीने तक कोई नई दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यह छह माह की अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बारे में संबंधित प्रावधानों को स्थगित करने पर फैसला अगले सप्ताह लिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से सरकार ने 25 मार्च से छह महीने के लिए संबंधित प्रावधानों को स्थगित करने का फैसला किया था। इसके लिए जून में अध्यादेश लाया गया था। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को ही लॉकडाउन लगाया गया था। इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह इस बारे में जून में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इन प्रावधानों का स्थगन अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है। सीतारमण ने कहा, "फिलहाल संहिता में संशोधन मुझे इसे सिर्फ एक साल तक विस्तार देने की अनुमति देता है। यह 25 सितंबर को समाप्त हो रहा है। 24 सितंबर को हमें घोषणा करनी होगी कि आगे क्या होगा। यदि मैं ऐसा करती भी हूं, तो मार्च में यह समाप्त हो जाएगा।" वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 25 मार्च से पहले कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से ऐसी कंपनियों को राहत नहीं मिलेगी। ज्यादातर विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से मांग की है कि कोविड-19 की वजह से संकट में फंसे किसानों और गरीबों लोगों को कर्ज पर ब्याज में छूट दी जाए। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने यह आशंका जताई कि कंपनियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों तथा व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ-साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। कुछ सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर सीतारमण ने कहा, "कई बार कर्ज लेने वाली कंपनियों की ओर कुछ गारंटर होते हैं। ऐसे में वृहद कॉरपोरेट दिवाला समाधान एवं परिसमापन के लिए हमारा मानना है कि जहां तक संभव हो, कॉरपोरेट कर्जदार और उसके गारंटर के खिलाफ साथ-साथ दिवाला कार्रवाई की जाए।" सदस्यों द्वारा यह पूछे जाने पर कि सबसे पहले यह अध्यादेश लाने की हड़बड़ी क्या थी, सीतारमण ने कहा, "विभिन्न सत्रों के बीच यदि जमीनी स्थिति की मांग होती है, तो अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ती है। एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व अध्यादेश का इस्तेमाल कर यह दिखाना होता है कि वह भारत के लोगों के साथ है।" वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण बनी स्थिति की वजह से समय की मांग थी कि तत्काल कदम उठाए जाएं और उसके लिए अध्यादेश का तरीका चुना गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार अगले ही सत्र में विधेयक लेकर आ गयी।

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 की वजह से कंपनियों को संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "ऐसे में हमने आईबीसी की धारा 7, 9, 10 को स्थगित करने का फैसला किया। इससे हम असाधारण परिस्थितियों की वजह से दिवाला होने जा रही कंपनियों को बचा पाए।" आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 किसी कंपनी के वित्तीय ऋणदाता, परिचालन के लिए कर्ज देने वालों को उसके खिलाफ दिवाला ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित है। मंत्री ने कहा कि आईबीसी अब कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कुछ आंकड़े देते हुए बताया कि अभी तक आईबीसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने कहा कि लोक अदालतों के जरिये 5.3 प्रतिशत ऋण की वसूली हुई। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के जरिये 3.5 प्रतिशत तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के जरिये 14.5 प्रतिशत की वसूली की गई। उन्होंने कहा कि वहीं आईबीसी के जरिये 42.5 प्रतिशत की वसूली हुई। उन्होंने कहा कि आईबीसी का मकसद कंपनियों को चलता हाल बनाए रखना है, उनका परिसमापन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आईबीसी प्रक्रिया के जरिये 258 कंपनियों को परिसमापन से बचाया जा सका। वहीं 965 कंपनियां परिसमापन की प्रक्रिया में गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन 258 कंपनियों को परिसमापन से बचाया गया, उनकी कुल संपत्तियां 96,000 करोड़ रुपये थीं। वहीं परिसमापन के लिए भेजी गई संपत्तियों का मूल्यांकन 38,000 करोड़ रुपये था। सीतारमण ने कहा कि मूल्य के हिसाब से देखा जाए, तो आईबीसी से जो संपत्तियां बचाई गईं, वे परिसमापन वाली संपत्तियों का ढाई गुना हैं। इस संशोधन के तहत आईबीसी की धारा 7, 9, 10 को कम से कम छह महीने तक स्थगित करने का प्रावधान है। इसे 25 मार्च 2020 से एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक नई धारा 10-ए को जोड़ा गया है। आईबीसी दिसंबर, 2016 में लागू हुआ था। अब तक इसमें पांच बार संशोधन किया जा चुका है।

बेहतर मानव संसाधनों के अभाव से जूझता भारत

राजकुमार जैन
कम्प्यूटर इंजीनियर

हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है बेहतर मानव संसाधनों की कमी, हमें शिकायत रहती है कि हमारे देश में बेहतर वैज्ञानिक नहीं हैं, हमारे पास बेहतर प्रबंधक नहीं हैं, हमारे नीति निर्धारक दोयम दर्जे के है, हमारे डॉक्टर सबसे अच्छे नहीं हैं, हमारे शैक्षणिक सांस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विहीन है आदि आदि, हम यह मानते हैं कि विदेशों में सब कुछ अच्छा है और हमेशा से हम इन कमियों का उत्तरदायित्व सरकार की रीति नीति को समझते आ रहे है, हम यह मानते है कि जिस देश में हम पैदा हए है, जिस देश ने हमें पाल पोसकर बड़ा किया, और एक हद तक शिक्षित बनाया उसी मातृभूमि की जब सेवा करने का अवसर आता है तब हमें हमारे अपने वतन में अपने लिए बेहतर अवसर नहीं दिखाई पड़ते हैं और देश को कुछ देने की बजाय हम यह कहकर विदेश जाना पसंद करते है कि मेरा देश मुझे क्या दे रहा है ?

अगर इस विषय पर ईमानदारी सहित गम्भीरता से इसकी तह तक जाकर समझा जाए तो वस्तुतःबेहतर मानव संसाधन की इस कमी की जिम्मेदारी हमारे अपने ही परिवारों पर आती है और यह एक बाहरी नहीं हमारी अपनी आंतरिक समस्या है, आइए समझते हैं ऐसा क्यों है...

हम हमेशा से यही चाहते आये है कि हमारा मेधावी, बुद्धिमान और कुशाग्र बच्चा आगे पढ़ने या पढाई के बाद नौकरी करने विदेश जाए और सम्भव हो तो विश्व के सबसे समृद्ध देश मे बस जाय । हमारी नजर में सफल कहलाने के लिए यही एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है, और तो और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अपने परिवार से बिछुड़ कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में है और इस कृत्य के लिए हम समाज में सम्मान भी पाते हैं ।

अब दूसरे देशों के हालात देखते है आपने कभी सुना कि जापानी वर्क फोर्स या केनेडियन लेबर या नार्वेजियन विशेषज्ञ या चीनी इंजीनियर या जर्मन वैज्ञानिक या अमरीकी डॉक्टर किसी और देश में जाकर उस देश की तरक्की में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा रहे हैं..... नहीं सुना ना, क्योंकि वहां देशप्रेम की भावना घर के अंदर से ही उपजती है, वहां देश को अपनी निजी सफलता से ऊपर माना जाता है, वहां के समाज में विदेश में जाकर विदेशियों के लिए काम करने को सम्मान की नजर से नही देखा जाता ।

हम भारतीय हर समस्या के लिए सिर्फ सरकार को दोष देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, क्या हमने कभी यह सोचा कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को अच्छे इंसान या बेहतरीन नागरिक बना रहे हैं (उस किस्म के गुणवान मानव जिनकी अपेक्षा हम दूसरों से करते है) जवाब है एक बड़ा नहीं बल्कि हम भारतीय अपने बच्चों को संस्कारों की बजाय भौतिक सुविधा और धन अर्जन को प्राथमिकता देने की शिक्षा देते हैं । हम अपनी आने वाली पीढी के मन में देशप्रेम का जज्बा भरने में पूर्णतया नाकाम रहे है, शायद नाकाम सही शब्द नहीं है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं और हम अपने बच्चों में देशप्रेम या देशभक्ति भरने का कोई प्रयास तक नही करते तो नाकाम कैसे हए ।

अब जब आप और हम स्वयम आगे बढ़कर और कई मामलों में बच्चों की अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर सिर्फ भौतिक सुविधाओं और धन के लालच में हमारी बेहतरीन सन्तानों (जो देश को बदल सकते हैं) को विदेशियों की सेवा चाकरी करने भेज रहें है तो फिर इन बची हुई कम योग्य सन्तानों द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम (जिसमे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यवसायी सभी शामिल) को बुरा भला कहने से क्या हासिल होगा । वो अंग्रेजी में कहते हैं ना what we get is what we deserve.

आप अच्छे परिणाम देने की उम्मीद किनसे कर रहे है वो लोग जो अपेक्षित रूप से सक्षम या उतने बुद्धिमान है ही नही, वो तो वही दे पाएंगे ना जो उन्हें आता है, जो संस्कार हमारे परिवारों ने अपनी संतानों को दिए है वो वैसा ही व्यवहार करेंगे ।

देखा जाय तो ये लोग जिनको गाहे बगाहे गरियाना हमारा प्रिय राष्ट्रीय शगल है वो भी हमारे अपने ही लोग हैं, ये हमारे गैर पसंदीदा अक्षम या भृष्ट लोग किसी दूसरे देश या ग्रह से तो अवतरित नहीं हए है, इनको परिवार से और समाज से जो शिक्षा मिली वही वो अब वापस लौटा रहे हैं ।

अपनी मेधावी संतानों को अपने ही देश में रहकर देश के विकास में योगदान देने को प्रेरित करने की संस्कृति अपनाए बगैर इस देश में वो बदलाव नही आ पायेगा जिसकी हम निरन्तर कल्पना करते रहते है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपनी ही पैदा की हुई स्थितियों से अपनी घनघोर नापसन्दगी जाहिर करते रहेंगे ।

तो मुद्दे की बात यह है कि देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, परिवार में सन्तान का लालन पालन जिस प्रकार हुआ है वैसे ही नागरिक हमें मिलते हैं, बात किसी एक परिवार की नहीं है इसे व्यापक रूप से देखना होगा, क्यों हमें ऐसे नागरिक मिल रहे हैं जिन्हें हम पसन्द नही करते, किसने पैदा किया इन्हें, किसने इन्हें पाला पोसा, किसने इन्हें बेईमान बनाया ? हमने ही ना ..... तो फिर कैसा शिकवा, किससे शिकायत, कौन दोषी ?

- जय जय

फ्लैट टेलीविजन होंगे अगले महीने से महंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

यदि आप टेलीविजन (ऊ्र) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसी महीने खरीद लीजिए। अगले माह अक्टूबर से टेलीविजन महंगे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार टेलीविजन के निर्माण में काम काम आने वाले ओपन सेल (ऊ्र ध्जह मत्त) पर 5 फीसदी का आयात शुल्क (घ्स्ज्दू अ्ल्ब) लगाने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आयातित ओपन सेल पर निर्भरता घटा कर इसका निर्माण यहीं किया जाए।

साल भर के लिए मिली थी छूट

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इस प्रोडक्ट पर नई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। दरअसल, इस पर ड्यूटी पहले से ही थी। लेकिन घरेलू टेलीविजन निर्माताओं को सहूलियत देने के लिए पिछले साल के लिए आयात शुल्क से छूट दी थी। ऐसा इसलिए, ताकि भारतीय निर्माता भी चीन और वियतनाम जैसे देशों से हो रहे सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह छूट की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। उसके बाद फिर से 5 फीसदी की ड्यूटी रिइंपोज (ा-ग्स्ज्दो) हो जाएगी।

हमेशा के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकते

वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि बिना शुल्क आयात की छूट आप हर समय नहीं ले सकते। पिछले साल जब यह छूट दी गई थी, तब यही समझा गया था कि इस अवधि में टेलीविजन कंपनियां यही इसे बनाने की तैयारी करेंगी। सरकार की योजना है कि यहां न सिर्फ टीवी के ओपन सेल, बल्कि अन्य कल-पुर्जे भी यहीं बने। तभी हमारी आयात पर निर्भरता घटेगी। वैसे भी इन चीजों के लिए हम हर समय विदेशों पर आश्रित नहीं रह सकते। इस दिशा में टीवी कंपनियों ने भी काम शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र की बड़ी कंपनी सैमसंग ने अपना मैन्यूफैक्चरिंग बेस वियतनाम से भारत शिफ्ट करने का फेसला किया है। इसके लिए कंपनी ने एक देशी कंपनी डिक्सन टेक्नोलोजिज से समझौता भी किया है।

कितनी बढ़ेगी कीमत

टीवी बनाने वालों (TV Manufactururs) का कहना है कि सरकार के इस फैसले से टीवी की कीमत बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि इस समय पूर्ण रूप से तैयार पैनल की कीमत 50 फीसदी तक बढ़ गयी है। ओपन सेल पर 5 फीसदी सीमा शुल्क लगाने से टेलीविजन की कीमत करीब 4 फीसदी बढ़ेगी। उनका कहना है कि इससे 32 इंच के टीवी के दाम में 600 रुपये और 42 इंच के दाम 1,200 से 1,500 रुपये का इजाफा होगा। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में और अधिक वृद्धि होगी।

प्रति टीवी 150 से 250 रुपये का फर्क पड़ेगा

वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टीवी कंपनियां ग्राहकों को सही सूचना नहीं दे रही हैं। इस समय प्रमुख ब्रांड 32 इंच के टीवी के लिये 2,700 रुपये और 42 इंच के लिये 4,000 से 4,500 रुपये की मूल कीमत पर ओपन सेल आयात कर रही हैं। ऐसे में अगर ओपन सेल पर 5 फीसदी की ड्यूटी लगाई जाती है तो यह 150 से 250 रुपये प्रति टीवी से अधिक नहीं होगा।

चीन ने API और KSM के दाम बढ़ाएं, आने वाले दिनों में महंगी होंगी दवाईयां

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि चीन पर निर्भरता अचानक से नहीं घट जाएगी। चीन इसी बात का समय-समय पर फायदा उठा रहा है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद API (Active Pharmaceutical Ingredients) और KSM (Key Starting Materials) का आयात चीन से किया जाता है।

20 फीसदी तक की तेजी

चीन ने की स्टार्टिंग मटीरियल की कीमत में 10-20 फीसदी का इजाफा किया है। इसका सीधा असर भारत में दवा की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अगले एक से दो महीने के भीतर जब ख्ए्श की नई खेप आएगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और दवा की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। उद्योग जगत का कहना है कि चीन का मकसद इस तरह की हरकतों से आत्मनिर्भरत भारत अभियान को धक्का पहुंचाना है।

KSM से एंटी बॉडी मेडिसिन तैयार होती है

भारत API का बड़े पैमाने पर आयात करता रहा है। API को बेसिक फार्म इंग्रीडिएंट कहते हैं। इसकी मदद से दवा तैयार होती है। एपीआई की कीमत अब प्री-कोविड लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत जरूरत का 70-80 फीसदी चीन से आयात करता है। ख्ए्श की मदद से भारतीय कंपनियां एंटीबॉडी तैयार मेडिसिन तैयार करती हैं। इसकी कीमत में तेजी के कारण दवा की कीमत में भी तेजी आएगी। इसकी कीमत में 15 फीसदी तक की तेजी आई है।

मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयातित सामान की कड़ी जांच

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आयात किये जाने वाले सामान के दस्तावेजों की सीमाशुल्क विभाग कड़ी जांच करेगा। इस कवायद का मकसद एफटीए के तहत आयातकों को मिलने वाली कर छूट के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब आयातकों को घरेलू सीमाशुल्क अधिकारियों को इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे कि जिस देश से सामान भारत में आयात किया गया उसने आयातित उत्पाद में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन किया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मोबाइल को इंडोनेशिया से भारत में आयात किया जाता है तो केवल ऐसे मोबाइल फोन के आयात को अनुमति होगी जिसका मूल उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ है और इंडोनेशिया में इसके उत्पादन में कम से कम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि वह जिस सामान का आयात कर रहे हैं उसके बारे में सुनिश्चित करें कि उसका विनिर्माण या उत्पादन निर्यात किए जाने वाले देश में हुआ है और उसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन उसी देश में किया गया है। इस बारे में आयातक को सभी दसतावेजी सबूत पेश करने होंगे और इसमें यह साबित करना होगा कि जिस देश से आयात किया गया है उसमें 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा किया गया है। केवल माल का "उत्पति प्रमाणपत्र" दिखाना ही काफी नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार के इस कदम की वजह घरेलू उद्योगों के कुछ तबकों की ओर 10 देशों के समूह आसियान के साथ हुये एफटीए के दुरुपयोग की लगातार की जा रही शिकायतें हैं।

इस्राइल-भारत प्रौद्योगिकी नवोन्मेष क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम

नयी दिल्ली। भारत के 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रोन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी' (आईक्रिएट) और इस्राइल के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देश नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी सहयोग को लेकर एक द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस्राइली दूतावास ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत और इस्राइल के उद्यमियों और स्टार्टअप को नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए साथ लाना है। इस सहमति ज्ञापन पत्र (एमओयू) पर यरूशलम से स्टार्टअप नेशन सेंट्रल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूजीन कांडेल और अहमदाबाद से आईक्रिएट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम जलोटे ने हस्ताक्षर किए। वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इस्राइल में भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंग्ला भी उपस्थित थे। इधर भारत में इस्राइल के राजदूत याकोव फिन्केल्स्टीन, इस्राइल के मुंबई स्थित महावाणिज्यदूत इस अवसर पर उपस्थित थे।

अधिक मास 2020

भगवान विष्णु देव की 20 पौराणिक बातें

1 . भगवान विष्णुसम्पूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं।

2. सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। यह सम्पूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी।

3. वे अपने चार हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं।

4. जो किरीट और कुण्डलों से विभूषित, पीताम्बरधारी, वनमाला तथा कौस्तुभमणि को धारण करने वाले, सुन्दर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है वह भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

5. मत्स्य अवतारपद्म पुराण के उत्तरखण्ड में वर्णन है कि भगवान श्री विष्णु ही परमार्थ तत्त्व हैं। वे ही ब्रह्मा और शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं।

6. जहां ब्रह्मा को विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है वहीं शिव को संहारक माना गया है। विष्णु की सहचारिणी लक्ष्मी है।

7. वे ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं।

8. कल्प के प्रारम्भ में एकमात्र सर्वव्यापी भगवान नारायण ही थे। वे ही सम्पूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करते हैं और अन्त में सबका संहार करते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम हरि है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, हयग्रीव तथा श्रीराम-कृष्ण आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं।

9. भगवान श्री विष्णु अत्यन्त दयालु हैं। वे अकारण ही जीवों पर करुणा-वृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है।

10. जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्चाविग्रह का दर्शन, वन्दन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप-ताप विनष्ट हो जाते हैं।

11.यद्यपि भगवान विष्णु के अनन्त गुण हैं, तथापि उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं, वे उनकी उस भावना को परिपूर्ण करते हैं।

12. मथुराध्रुव, प्रह्लाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्तों का उनकी कृपा से उद्धार हुआ।

13. भक्त वत्सल भगवान को भक्तों का कल्याण करनें में यदि विलंब हो जाए तो भगवान उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिए क्षमा-याचना करते हैं। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता।

14. मत्स्य, कूर्म, वाराह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की कथाओं में भगवान श्री विष्णु की भक्त वत्सलता के अनेक आख्यान आये हैं। ये जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। वेदों में इन्हीं भगवान श्री विष्णु की अनन्त महिमा का गान किया गया है।

15. विष्णुविष्णुधर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि लवण समुद्र के मध्य में विष्णु लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें भगवान श्री विष्णु वर्षा ऋतु के चार मासों में लक्ष्मी द्वारा सेवित होकर शेषशय्या पर शयन करते हैं।

16. पद्म पुराण के उत्तरखण्ड के 228वें अध्याय में भगवान विष्णु के निवास का वर्णन है।

17. वैकुण्ठ धाम के अन्तर्गत अयोध्यापुरी में एक दिव्य मण्डप है। मण्डप के मध्य भाग में रमणीय सिंहासन है। वेदमय धर्मादि देवता उस सिंहासन को नित्य घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य सभी वहां उपस्थित रहते हैं। मण्डप के मध्यभाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। कूर्म, नागराज तथा सम्पूर्ण वेद वहां पीठ रूप धारण करके उपस्थित रहते हैं।

18. सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है; जिस पर देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं।

19. भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए जप का प्रमुख मंत्र- ॐ नमो नारायणाय तथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय है।

20. भृगु द्वारा त्रिदेवपरीक्षा से देवताओं ने माना कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

हनुमान चालीसा में छुपे हैं सेहत के 10 रहस्य

लॉकडाउन के चलते वर्तमान समय में लोगों के मन में शंका, भय, निराशा, अनिश्चितता, क्रोध और कई तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी से रोग लग जाता है। ऐसे में किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपका फायदा कर सकता है, जानिए सेहत के 10 रहस्य।

1. आध्यात्मिक बल : कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है। साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है।

2. मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा : नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होना है हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना यह सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति हैं- अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता।

3. अकारण भय व तनाव मिटता : हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है- भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। या सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है।

4. हर तरह का रोग मिटता : हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है- नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत बीरा। या बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो आप बस श्रद्धापूर्वक हनुमानजी का जाप करते रहे। हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेस हो अर्थात कष्ट हो, वह सम्पात हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब यह कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी।

5.हर तरह का संकट मिटता : आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें- संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या संकट तें हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगी।

6. बंधन मुक्ति का उपाय : कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है- जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बन्दि महा सुख होई। सत अर्थात सौ।

7. नकारात्माक प्रभाव होते हैं दूर : मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है।

8. ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर : ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं। जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम-ज्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मनसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियमपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है।

9. घर का कलह मिटता है : यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है। कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है।

10. बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा : यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालन। जब व्यक्ति तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे-धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है।

पुनश्च : नित्य हनुमान चालीसा बढ़ने से आपमें आध्यात्मि बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इसे पवित्रता की भावना महसूस होती है। शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है।

आवासीय भवनों में निर्माण के दौरान ही विकसित किया जाए दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचाः ट्राई

नयी दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख आर. एस. शर्मा का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों में कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। उनका सुझाव है कि बहुमंजिला आवासीय भवनों में नागरिक कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूए) को दूरसंचार क्षेत्र के सभी परिचालकों को साझा बुनियादी ढांचा खड़ा करने की अनुमति देनी चाहिये। शर्मा ने कहा कि लोगों की आम धारणा यह है कि एक बार मोबाइल टावर लग जायेगा तो कनेक्टिविटी संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुमंजिला भवनों में दूरसंचार संपर्क की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसलिए आरडब्ल्यूए को चाहिए कि वह इमारतों के निर्माण की योजना के दौरान ही बिजली, पानी और अन्य सेवाओं की तरह ही कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को भी शामिल करें। यह ढांचा साझा करने लायक हो ताकि सभी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। शर्मा ट्राई के दो परिचर्चा पत्रों के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। इसमें एक परिचर्चा पत्र बहुमंजिला आवासीय इमारतों में कनेक्टिविटी की अच्छी गुणवत्ता से जुड़ा है। ट्राई प्रमुख ने कहा कि आम धारणा यह है कि मोबाइल टावर की मौजूदगी सभी समस्याओं का निराकरण कर देगी।

लेकिन इमारतों के भीतर कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा, ''लोगों का मानना है कि एक बार टावर आ जाएगा, सब कुछ काम करने लगेगा। यह एक मिथक है। पहले लंबी-लंबी इमारतें बन जाती हैं और उसके बाद हम कनेक्टिविटी के बारे में सोचते हैं।'' शर्मा ने कहा कि कई बार तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर ही मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। यह समस्या सिर्फ बहुमंजिला आवासीय इमारतों की ही नहीं, बल्कि अस्पतालों, मॉल और उप-नगरीय क्षेत्रों में स्थित कार्यालयी इमारतों में भी है। उन्होंने कहा कि इसका दीर्घावधि में एक ही समाधान है और वह है फाइबर कनेक्टिविटी। ट्राई प्रमुख ने कहा, '' मेरा मानना है कि पारंपरिक तौर पर हम बिजली, पानी और केबल टीवी की लाइन को ही प्राथमिकता देते हैं, जब किसी इमारत का निर्माण हो रहा होता है तो हम इन सबके लिए प्रावधान करते हैं लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वॉयस और डेटा कनेक्टिविटी के लिये ऐसा प्रावधान नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोच है कि यह सब मोबाइल टावर से काम करेगा।'' उन्होंने कहा कि असल में पर्याप्त मात्रा में टावरों की संख्या भी अच्छी गुणवत्ता का नेटवर्क तैयार नहीं करेगी। इसका समाधान नीति और व्यवहार में बदलाव लाकर हो सकता है।

शर्मा ने कहा कि आरडब्ल्यूए दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को अपार्टमेंट में प्रवेश देने के लिए के लिए शुल्क वसूलते हैं। उन्हें लगता है कि इससे होने वाली आय से वह लोगों को अधिक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन यह चीजों को दूसरे तरीके से देखने का नजरिया है। रहवासियों को अच्छी सुविधाएं तब मिलेगी जब उनकी कनेक्टिविटी की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह आरडब्ल्यूए के हित में होगा कि वे अपनी इमारतों में हर दूरसंचार सेवाप्रदाता को प्रवेश का मौका दें। इन सभी कंपनियों को दूरसंचार से जुड़ा एक साझा करने लायक बुनियादी ढांचा बनाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि इन्हें अपनी सेवा उपलब्ध कराने में 'बटन खोलने और बंद करने' जितनी आसानी हो।

कोविड-19 टीके के लिए विनिर्माण सुविधाओं पर 5 हजार करोड़ रुपये तक निवेश की जरूरतः जायडस कैडिला

नयी दिल्ली। एजेंसी

दुनिया में कोविड-19 के टीके का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वहीं जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने कहा है कि भारत को अपने आबादी को व्यापक रूप से इस महामारी का टीका उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के विकास पर 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही पटेल ने कहा कि वैक्सीन या टीका कोविड-19 समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। पटेल ने कहा कि भारत को यदि एक साल में 130 करोड़ लोगों को इसकी खुराक की आपूर्ति करनी होगी, तो मेरी राय में हमें विनिर्माण सुविधाओं पर 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना होगा।

अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान (एआईएमए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ''कोविड वैक्सीन के लिए दौड़ः सिर्फ इलाज से कहीं अधिक' पर पैनल चर्चा में पटेल ने कहा कि ये वैक्सीन काफी मुश्किल प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। इस टीके की लागत अन्य वैक्सीन की तुलना में कहीं अधिक होगी। ऐसे में यह सोचने की जरूरत है कि हम इसका वित्तपोषण किस तरह से करेंगे।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह टीका महामारी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटेल ने कहा, ''मेरे विचार में सिर्फ वैक्सीन समस्या का समाधान नहीं है। हमें टीके की जरूरत तो है, साथ ही इलाज के प्रोटोकॉल की भी जरूरत है, जिससे हमें इसे संभाल पाएं। मेरी राय में दुनिया में जिस तरह से इस टीके के परीक्षण को डिजाइन किया गया है, ऐसे में 100 प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की संभावना नहीं बनती है।'' पटेल ने कहा कि इस टीके की आवश्यकता भी काफी ऊंची होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुये की सभी टीके की कम से कम दो खुराक देनी होगी। यदि हम भारत की आबादी को देखें और 50 प्रतिशत को इसे उपलब्ध कराना है तो हमें 130 करोड़ से अधिक खुराक चाहिये। इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है। यदि क्षमता हो भी तो भी इसे एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकता है। यह केवल लंबे समय में ही हो सकता है। यह भी देखने की जरूरत है कि टीके से रोक प्रतिरोधक क्षमता कितने समय तक बनी रहेगी। यदि यह टीके से लंबे समय तक रहती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि अल्प समय के लिये ही होती है तो हमें बार बार लोगों को टीका देना होगा, यह चुनौती होगी।

वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ भारतीय कंपनियां ही लगा सकती हैं बोली, चीन को इजाजत नहीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे 44 वंदे भारत ट्रेनों के लिए 2000 करोड़ रुपये की बोली मंगा रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी बिडिंग मानी जा रही है। इसमें सिर्फ देसी कंपनियां ही बोली लगा सकती हैं। बता दें कि इससे पहले चीन की ण्ण कंपनी ने भी इसमें बिडिंग के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि इसमें बोली सिर्फ भारतीय कंपनियां ही लगाएंगी। इसकी बिडिंग ऑनलाइन होगी और ये लाइव होगी। जो सबसे कम बोली लगाएगी, उस कंपनी को ये ट्रेनें बनाने का टेंडर मिल जाएगा।

सोमवार को जारी हुए रिवाज्ड टेंडर को घरेलू दो वजहों से कहा जा रहा है। पहला ये कि इसमें 75 फीसदी लोकल कंटेंट होगा, जबकि इससे पहले बिड में 50 फीसदी लोकल कंटेंट रखने की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी वजह ये है कि सिर्फ भारतीय कंपनियां ही इस टेंडर के लिए बोली लगा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके। टेंडर के अनुसार ये ट्रेनें आईसीएफ चेन्नई, आरसीएफ कपूरथला और एमसीएफ राय बरेली में बनाई जाएंगी। इस टेंडर में बोली लगाने के लिए कंपनियों को पहला चरण पार करना होगा, उसके बाद ही बोली लगाने की इजाजत होगी।

इस वर्ल्ड हार्ट डे पर बादाम खाकर अपने दिल को स्वस्थ बनाएं

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ताकि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज (सीवीडी) और उनकी रोकथाम पर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। वर्ल्डल हार्ट डे दुनियाभर के लोगों को याद दिलाता है कि वे अपने और अपने परिवार के लिये लाइफस्टा।इल से संबंधित विकल्पोंन का मूल्यांयकन करना शुरू करें और इस रोग से अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिये कठोर कदम उठाने की जरूरत को पहचानें।

शोध से पता चला है कि अपनी आनुवांशिकी के कारण भारतीय हृदय रोगों के लिये ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कई भारतीय परिवारों के लिये स्वास्थ्य सम्बंधी एक गंभीर चिंता बन रहे हैं, लेकिन बदलाव लाने और जोखिम के कारकों को कम करने में डाइट तथा जीवनशैली से सम्बंधित सुधार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ताकि हृदय का स्वास्थ्य बेहतर हो। दुनियाभर के लोग न्यू नॉर्मल के अनुकूल बनने के लिये अपनी लाइफस्टा इल में बदलाव कर रहे हैं और स्वास्थ्य की देखभाल करना किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर करने का पहला चरण है हृदय को स्वस्थ रखने वाले आहार लेना। अपने और परिवार की रोजाना की डाइट में एक मुट्ठी बादाम जैसे नट्स शामिल करना अच्छी शुरूआत हो सकता है, क्योंकि बादाम में कई पोषक-तत्व होते हैं, जो उसे स्नैकिंग का एक स्वास्थ्यकर विकल्प बनाते हैं और आपके हृदय के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं।

हृदय को स्वस्थ रखने वाली जीवनशैली के महत्व के बारे में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोहा अली खान ने कहा, ''कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भारत के परिवारों में आम होती जा रही हैं। लाइफस्टाइल और आहार में छोटे, लेकिन प्रभावी बदलाव कर हम खुद को और अपने परिवार को सीवीडी से बचाने के लिये सार्थक प्रयास कर सकते हैं। और इसके सबसे आसान तरीकों में से एक है अपनी डाइट में बादाम जैसे हेल्दीथ फूड्स शामिल करना। बादाम 14 मौलिक पोषक-तत्वों का स्रोत होते हैं, जैसे विटामिन 'ई', मैग्नीशियम, प्रोटीन, रिबोफ्लेविन, जिंक, आदि। शोध भी कहता है कि बादाम के नियमित सेवन से एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करने में प्रभावी मदद मिल सकती है, जिससे बीतते समय के साथ आपका और आपके परिवार का हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होगा।''

फिटनेस और सेलीब्रिटी इंस्ट्रक्टर यास्मिन कराचीवाला के अनुसार, ''सही वजन बनाये रखकर आप डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉयल और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम कम कर सकते हैं - इन सभी का कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से सम्बंध है। इसके लिये, मैं रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्स रसाइज करने की सलाह देती हूँ, ताकि आपका शरीर ऐसे आकार में आये, जो आपको अच्छा लगता हो। रोज एक्स?रसाइज करने के लिये पैदल चलने, दौड़ने, योग, पाइलेट्स या ऑनलाइन डांस क्लास का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा, पौष्टिक और संपूर्ण आहार लें, जैसे बादाम। बादाम से सेहत को कई तरह के लाभ होते हैं और रोजाना एक मुट्ठी बादाम खाने से आपके हृदय का स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहेगा।''

न्यूट्रीशन एंड वेलनेस कंसल्टेन्ट शीला कृष्णास्वामी ने सही खाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''हृदय के स्वास्थ्य पर लगातार फोकस करना चाहिये और लाइफस्टाजइल में लंबी अवधि के बदलावों पर जोर देना चाहिये। हृदय को स्वस्थ रखने के लिये, अन्य कामों के अलावा अपने वजन की जांच करते रहना महत्वपूर्ण है। साल 2015 के एक अध्ययन ने बताया कि रोजाना 42 ग्राम बादाम खाने से पेट की चर्बी और कमर का नाप कम हुआ, जो कि हृदय रोग के जोखिम के कारक हैं।

कोका-कोला ने मप्र के अलीराजपुर में नदी के पुनरुद्धार के लिए की मदद

साढ़े आठ हजार से ज्यादा जिंदगियां होंगी लाभान्वित

अलीराजपुर। आईपीटी नेटवर्क

राजपुताना सोसाइटी ऑफ नैचुरल हिस्ट्री भरतपुर (आरएसएनएच) के साथ साझेदारी में भारत में अपने जल प्रबंध कार्यक्रमों को तेज करते हुए कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन आनंदना ने मध्य प्रदेश के जिले अलीराजपुर में सुखाड़ नदी के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं के विकास के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। एक स्थायी मॉडल बनाने के उद्देश्य से, सुखाड़ परियोजना उस समुदाय के लिए पीने और कृषि के लिए इष्टतम पानी की सुविधा प्रदान करेगी जो भोजन और आजीविका की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। महामारी की चुनौतियों के दौरान, इस परियोजना ने 8500 से ज्यादा लोगों और 1400 से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किया, जो कि सेजगांव, राजावत, पलवत, तलवात, तीती और खारपई गांवों में लगभग 93 फीसदी देशज आबादी हैं। इसके अतिरिक्त, इसने एक अरब लीटर से अधिक वर्षा जल संचयन को संभव बनाया है, जिससे 95 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। इसके अलावा, इसने महामारी और प्रतिबंधों के इस दौर में ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं।

मध्यप्रदेश के कुछ चुनिंदा जिले ऐसे हैं, जो भीषण जल संकट और बड़े पैमाने पर प्रवासन के लिए जाने जाते हैं और सरकार द्वारा देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। मानव विकास सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहे, अलीराजपुर जिले में रहने वाले समुदाय वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत वर्षा आधारित कृषि है। क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धता की वजह से किसानों की कृषि उपज में कमी और इस वजह से उनकी आय में काफी गिरावट आई है। जल संरक्षण के लिए उचित योजना और सुविधाओं की कमी की संयुक्त वजह से समुदायों को पानी हासिल करने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। इससे उनकी खेती आर्थिक तौर पर अस्थिर बनती जा रही है।

कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन, आनंदना ने छोटी-छोटी नदियों के पुनरुद्धार का काम अपने हाथ में लिया और पीने, कृषि और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रचुर पानी की सुविधा प्रदान की है। जलग्रहण क्षेत्र में निर्मित दो चेक डैम और अन्य संरचनाओं से न केवल पानी की भारी मात्रा का संरक्षण हुआ बल्कि भूजल स्तर को फिर से भरने में मदद भी मिली। इसके फलस्वरूप वनस्पतियों और जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का पुनरुद्धार हो सकेगा। संरक्षित पानी संभावित रूप से कम से कम दो मौसमों के लिए समुदायों के काम आएगा और किसान अब हर साल दो फसलों की खेती कर सकते हैं।

सुखाड़ पुनरुद्धार परियोजना के सफल समापन पर टिप्पणी करते हुए, कोका-कोला इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट, पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशसं एंड सस्टैनबिलिटी, इश्तियाक अमजद ने कहा, 'भारत की जल चुनौती को दूर करने के लिए जल संरक्षण सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। भारत भर में स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन (आनंदना) ने पिछले 10 वर्षों से इसके लिए हर मुमकिन योगदान दिया है। इस प्रकार हमने अब तक 550 से ज्यादा गाँवों में 13 बिलियन लीटर पानी के भंडारण की क्षमता पैदा की है, जिससे आठ लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। हमारा मानना है, टिकाऊ और प्रभावी जल प्रबंधन समाधान खोजने के लिए सरकारों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे साथी राजपुताना सोसाइटी ऑफ नैचुरल हिस्ट्री ने हमें परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने और अलीराजपुर जिले के समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद की है। हम समुदाय और पर्यावरण के लिए योगदान करने की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखेंगे। कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन आनंदना बड़े पैमाने पर समुदायों के समग्र विकास के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। 2007 में अपनी स्थापना के बाद से, फाउंडेशन ने सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता और पोषण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने स्थायित्वपूर्णता के प्रयासों को विकसित और संरेखित किया है।

वंडरएक्स ऐप के जरिये अपने वैक्सिनेशन की प्री बुकिंग करें

अब लोग नजदीकी क्लीनिक में वैक्सीन के लिए वर्चुअली अपाइंटमेंट ले सकते हैं

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मुम्बई के एक हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप ने भारतीय नागरिकों के लिए अपना वैक्सिनेशन करवाने के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर या वैक्सिनेशन क्लिनिक से अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक एप्लिकेशन लॉन्च किया है।अति आवश्यक सुविधाओं और पारदर्शिता प्रदान करते हुए, यह प्लेटफॉर्म भारत के हर कोने तक वैक्सिनेशन को सुनिश्चित करेगा। हेल्थ-टेक फर्म, वंडरएक्स, ने एक एप के जरिये यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आसानी से वैक्सीन मिल सके, जिसके लिए वंडरएक्स ने देश भर में डॉक्टरों और योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ करार किया है। वंडरएक्स ने पहले ही अपने वंडरएक्सउपभोक्ता ऐप पर 180 हजार से अधिक हेल्थकेयर प्रदाताओं की सूची तैयार कर ली है, जिससे यह भारत में हेल्थकेयर प्रदाताओं का सबसे बड़ा एग्रीगेटर बन गया है।

इस अवसर पर, वंडरएक्स के सह-संस्थापक और निदेशक, श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि 'हमारा ऐप हमारे द्वारा चुने गये वैक्सिनेशन क्लीनिकों के विवरणों की सूची बनायेगा,और इसके अंतर्गत वैक्सिनेशन के लिए प्री-बुकिंग टाइम स्लॉट में फीस जमा करनी होगी। प्री-बुकिंगस्लॉट के माध्यम से वैक्सिनेशन के लिए बुकिंग सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखते हुए भीड़ का प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। इस देश के हर कोने के लोग दिए गए विवरणों के आधार पर एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे।'

उन्होंने कहा कि "हमारा ऐप प्रत्येक राज्य के निवासियों और वैक्सिनेशन क्लीनिकों के बीच एक पुल का काम करेगा। इससे लोगों को अपनी पसंद के वैक्सिनेशन क्लीनिक के साथ अपनी बुकिंग करने में मदद मिलेगी और लोग अनिश्चितताओं में पड़े रहने और लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने से बचेंगे।" ऐप पहले चरण में एंड्रॉइड फोन के साथ सक्रिय होगा और बाद के चरणों में आईओएस संस्करण लॉन्च किए जाएंगे। यह ऐप इस देश के प्रत्येक उपभोक्ता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकेगा। इस उत्पाद के लाभों के बारे में बताते हुए,वंडरएक्स के संस्थापक और निदेशक, श्री पंकज सिंधु ने कहा कि 'यह उत्पाद उपभोक्ता, डॉक्टर, वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूटर और निर्माता सभी के लिए वैक्सिनेशन को काफी सुविधाजनक बनायेगा और वैक्सिनेशन को लेकर आवश्यक पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक नियंत्रण और दृश्यता प्रदान करेगा और एक नियंत्रित सप्लाई चेन बनायेगा।' वंडरएक्स डिजिटल इंडिया की सोच पर आधारित, भारत में बना एक हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप है जो देश में हेल्थकेयर स्टेकहोल्डर्स के बीच 'आत्मनिर्भर' की अवधारणा को बढ़ाने का काम कर रहा है।

... और सस्ता हो गया सोना, चांदी 3 दिन में 7688 रुपये हुई सस्ती

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। देश भर के सर्राफा बाजारों में आज यानी बुधवार को 24 कैरेट सोना 461 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे खुला। वहीं चांदी के रेट में 1742 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। सोने का हाजिर भाव 50222 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 58217 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। पिछले तीन दिन में सोने के भाव में 1398 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, वहीं चांदी 7688 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक 23 सितंबर 2020 को देशभर के सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के हाजिर भाव Gold 999 (24 कैरेट) 50222 रहे जो कि 22 को 50683 थे इसमें 461/- की कमी आई। बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी (GST) शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ibja देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। खोसला कहते हैं कि सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है।

ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को नहीं होगी परमिट की जरूरत, सरकार ने दी छूट

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट देने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इस कदम से देशभर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा, 'राज्यों के बीच तथा राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंक की आपूर्ति करने वाले वाहनों को 31 मार्च, 2021 तक परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।' बयान में कहा गया है कि इस महामारी के समय इलाज के लिए ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। बयान के मुताबिक मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि परिवहन ऑपरेटरों को इस बारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के अनुरूप मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून, 1988 की धारा 66 के तहत इन वाहनों को परमिट से छूट को लेकर अधिसूचना जारी की है।

कोरोना के कुल मामले

देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख 87 हजार 580 हो गई है। इनमें से 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख 3 हजार है और 43 लाख 96 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब चार गुना अधिक है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।